(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) पुलिस द्वारा एक मामला दर्ज किया गया है और उपद्रवियों को पकड़ने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

STRIKE BY HARYANA GOVERNMENT EMPLOYEES

2501. SHRI K. RAMANI :
SHRI SHRI CHAND GOEL :
SHRI SURAJ BHAN :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the employees of the Haryana Government went on strike on the 8th and 9th February, 1968;

(b) if so, the total number of employees who participated in the strike;

(c) their demands; and

(d) the steps taken by Government to settle the dispute ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Yes, Sir.

(b) and (d). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-294/68].

SAINIK SCHOOLS SCHOLARSHIPS

2502. SHRI KANWAR LAL GUPTA :
SHRI GADILINGANA GOWD :
SHRI JYOTIRMOY BASU :
DR. KARNI SINGH :
SHRI N. K. SOMANI :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of boys selected this year for admission to the Sainik Schools from the Union Territories on the basis of all-India examination;

(b) whether it is a fact that as against 140 scholarships granted last year by the Ministry of Home Affairs only 40 scholarships have been granted this year to these boys;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) whether Government have any scheme to give financial assistance to the boys belonging to the lower income groups who have been denied scholarships this year and whose parents cannot afford to pay the full fee to these schools; and

(e) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) 103 boys qualified for admission to various Sainik Schools on the basis of an all India test.

(b) and (c). According to the scheme of Union Territories' Scholarships, 126 scholarships were sanctioned. Owing to the pressure of admissions last year, purely as a temporary measure, the number of scholarships was raised to 265, with the result that 139 new scholarships were granted last year. Out of these only 40 were available for sanction this year, since this number was surrendered last year. The question of accommodating the remaining boys who are otherwise eligible, is under the consideration of the Government of India.

(d) and (e). The present scholarships will be confined to those students whose parents earn income of Rs. 500 per month or less. The definition of this income excludes all types of allowances including dearness allowance.

---

12-0 HRS.

## CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

ALLEGED OCCUPATION OF INDIAN ISLAND BY CEYLON

**श्री ओ० प्र० त्यागी (मुरादाबाद)** : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर वैदेशिक-कार्य

**[श्री ओ० प्र० त्यागी]**

मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"श्री लंका द्वारा पाक स्टेट में एक भारतीय द्वीप पर कब्जा किया जाना।"

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI B. R. BHAGAT) : The attention of the Government has been drawn to a newspaper report of the 29th February, 1968 alleging that the Government of Ceylon is now acting "on the full assumption" that it has complete ownership of the Kuchchativu Island in the Palk Straits between India and Ceylon.

2. The matter is under examination and is being taken up with the Ceylon Government. We have asked our High Commissioner in Ceylon to find out from Ceylon Government the truth of this report.

**श्री ओ० प्र० त्यागी** : अध्यक्ष महोदय, देश के सामने यह कोई छोटे से टापू का प्रश्न नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा महत्व है और वह यह कि पिछले 20 वर्षों के इतिहास में भारतवर्ष में जो घटनायें घट रही हैं विदेशों के द्वारा, उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष एक धर्मशाला है जहां जिसके जी में आए अपना बिस्तरा रख ले और जबतक जी में आए रखे रहे। धर्मशाला के भी कुछ नियम होते हैं लेकिन भारतवर्ष का यह हाल है कि हमारे पड़ोसी जो देश है वे हमारी भूमि पर कब्जा कर लेते हैं फिर यहां की सरकार या तो प्रोटैस्ट करती है या इस चीज का बहाना लेकर कि वार हो जाएगी या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को हानि होगी, उस भूमि को उन्हें सौंप देती है। अध्यक्ष महोदय, हिन्द महासागर में बहुत से ऐसे टापू हैं जिनपर अमरीका का, चाइना का और पाकिस्तान का दावा है और उन्हीं टापुओं में से एक टापू पर यह बात आई है कि सीलोन ने उस टापू पर अधिकार किया है जिस पर कि भारतवर्ष और सीलोन की सरकारें अपने अधिकार को मान्यता देती हैं। सीलोन की सरकार ने अपने अधिकार से उस टापू पर अपना अधिकार जमा लिया है। यह एक बहुत बड़ा ऐसा कार्य हुआ है जोकि भारतवर्ष की सावरेन्टी को चेलेन्ज करता है। सरकार की ओर से जैसा कि अभी जवाब दिया गया कि यहां की सरकार ने सीलोन की सरकार को लिखा है, उनसे पत्र-व्यवहार किया है और अपने हाई कमिश्नर से भी कहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब उन्होंने अधिकार जमा लिया है तब आप प्रोटैस्ट कर रहे हैं। मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि भारतवर्ष में आपने हिन्द महासागर में स्थित उन द्वीपों, जिनपर कि अमरीका पाकिस्तान आदि की प्रोटैस्ट है, की रक्षा के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है और ऐसे टापू के सम्बन्ध में सरकार क्या ऐक्शन लेने जा रही है ?

**श्री ब० रा० भगत**: यह मामला भारत सरकार और सीलोन सरकार के बीच में है। मैं माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भारत और सीलोन के बीच में हैं उनके तहत मजबूर न करें.... (**व्यवधान**).....कि बिना जानकारी किए हुए सरकार की ओर से कोई बात कही जाए। .... (**व्यवधान**) देने का सवाल तो अभी उठता ही नहीं।

**एक माननीय सदस्य**: अखबारों में निकला है...

**श्री ब० रा० भगत**: अखबारों की सभी खबरें सही नहीं हुआ करतीं। हम सीलोन सरकार से इस सम्बन्ध में बातचीत करेंगे और जैसे ही पूरी सूचना हासिल हो जाएगी, उसको सदन के सामने रखेंगे।

**श्री ओ० प्र० त्यागी** : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने मेरे प्रश्न का पूरा जवाब नहीं दिया है। मैंने पूछा है कि इसी प्रकार के जो अन्य द्वीप हैं जिनपर अमरीका पाकिस्तान आदि की प्रोटेस्ट है, उनकी रक्षा के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

MR. SPEAKER : That has nothing to do with Ceylon.

**श्री कामेश्वर सिंह (खगरिया)** : क्या प्रधान मन्त्री बताएंगी कि यह तो एक छोटे आईलैंड के लिए कहा गया कि इन्होंने सीलोन से पूछा है लेकिन प्रधान मन्त्री को इस बड़े देश के किसी भी भाग के लिए कोई भी मोह माया नहीं है, जो उन का रुख है उस से मुझे तो ऐसा समझ में आता है कि जैसे विनोभा जी भूमिदान देते हैं, उसी प्रकार से इन का रुख तो भारत-दान का है, सारे भारतवर्ष को ही ये दान करना चाहती हैं। सीलोन ने उस छोटे से आइलैंड को ले लिया जो कि भारत का था, तो मैं जानना चाहता हूं कि उस के लिए आपने पहले से ही कोई इन्तजाम क्यों नहीं किया था? आप वहां नौसेना क्यों नहीं भेजते हैं? .... (**व्यवधान**) ... अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसे कितने द्वीप हैं, हिन्द महासागर में, भारत के 400 मील दक्षिण तक जिन पर कि कमजोरी के कारण भारत सरकार का अधिकार खत्म हो गया है?

**श्री ब० रा० भगत** : यह इल्जाम सरासर गलत है कि कोई भूमि दान की जा रही है। आपका दूसरा सवाल यह है कि ऐसे कितने द्वीप हैं जिनको हम दूसरों को दे रहे हैं, इस में भी कोई सच्चाई नहीं है।

**श्री जार्ज फरनान्डीज (बम्बई-दक्षिण)** : एक तरफ तो कच्छ का मामला जैसे खत्म होता जा रहा है, वैसे ही पाकिस्तान ने अभी अण्डमान और निकोबार के ऊपर अपनी मांग पेश की है। 23 तारीख को हिन्दुस्तान टाइम्ज में पाकिस्तान सरकार की ओर से चलाये जानेवाले प्रेस-पाकिस्तान नाम की जो संस्था है.....

MR. SPEAKER : Why don't you come to Ceylon?

**श्री जार्ज फरनान्डीज** : अध्यक्ष महोदय, ये सारी चीजें एक दूसरे से मिली हुई हैं। यह देश के संरक्षण का मामला है।

अब पाकिस्तान का यह कहना है कि अंडेमान, निकोबार का बंटवारा होना चाहिए। चार देशों में उस का बंटवारा होना चाहिए। इंडोनेशिया, बर्मा, पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में और वे लोग यह बतलाते हैं :

> "According to the press of Pakistan, the closest of these islands in the Bay of Bengallies some 750 miles away from Bengal, 740 miles from Madras while these are only 100 miles away from Indonesia, 120 miles from Burma and 425 miles from East Pakistan. The article recommends that the administration of Andaman and Nicobar Islands therefore be handed over to the country closest to that."

**श्री जार्ज फरनेन्डीज** : अब अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है.....

SHRI K. R. GANESH (Andaman and Nicobar Islands) : Sir, on a point of order. I had given notice of a Calling Attention on this.

MR. SPEAKER : No, I will not allow it now.

SHRI K. R. GANESH : Your office has rejected my calling attention notice. Yet, you allow it to be raised here by some other hon. Members. I am sorry; this is happening.

MR. SPEAKER : But there is no point of order.

SHRI K. R. GANESH : While you did not admit my calling attention notice, you are allowing this to be raised on a calling attention which has nothing to do with this subject.

MR. SPEAKER : I would request Shri Fernandez to confine his question to Ceylon. He cannot bring in the whole foreign policy of India.

**श्री जार्ज फरनेन्डीज** : अध्यक्ष महोदय, मैं इस देश की भूमि के संरक्षण के बारे में पूछ रहा हूं। अब इन को समझ न हो तो मैं क्या करूं? बस प्वाएंट आफ आर्डर बिना जाने बूझे उठा दिया। मैं इस देश के संरक्षण के बारे में पूछ रहा हूं.....

MR. SPEAKER : If he asks this question, others take objection to it. Here is a Member who comes from Andamans and he is raising it.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal) : I am rising on a point of order under rule 197(2). When a Calling Attention Notice has been tabled and is being answered by the Minister there shall be no debate on that statement. Now the hon. Member is converting this calling attention into a debate.

MR. SPEAKER : I agree with the hon. Member. This Calling Attention is about Ceylon. We are not discussing the entire foreign policy of Pakistan claiming something or China claiming something else. He can ask for some clarification about Ceylon. I am not going to allow anything beyond that.

**श्री जार्ज फरनेन्डीज** : ठीक है तब मेरा यह प्रश्न है. . . . . .

**श्री मधु लिमये** (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना है। अंडेमान के बारे में हम लोगों ने एक ध्यानाकर्षण नोटिस अलग दिया था । मुझे इत्तिला मिली है कि वह मंजूर नहीं किया जाएगा . . . . .

MR. SPEAKER : That is a different matter. On that account you cannot bring this.

**श्री मधु लिमये** : फिर हम कब उठायें ?

MR. SPEAKER : That is exactly what Shri Ganesh raised. I did not allow him. So, he cannot also raise it on that account.

**श्री मधु लिमये** : उसे क्यों नहीं मंजूर किया गया ?

**श्री जार्ज फरनेन्डीज** : अभी मन्त्री महोदय ने ऐसा बतलाया है कि सीलोन में अपने हाई कमिश्नर को लिख भेजा है और उन से कहा है कि वह जरा इस की तलाश कर लें । लेकिन मेरा कहना है कि वह मामला हाई कमिश्नर के तलाश करने का नहीं है। कल बजट में 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक रुपया हिन्दुस्तान की भू सेना, नौ सेना और हवाई सेना के वास्ते मंजूर करने की मांग की गई है। क्या हिन्दुस्तान की कोई सेना नहीं है और क्या आप वहां पर जहाज नहीं भेज सकते हैं और अगर उस भूमि को सीलोन ने अपने हाथ में लिया हो तो तत्काल उस को वापिस कराने के लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं ।

साथ-साथ यह अंडमान और निकोबार के बारे में कहीं वही बात तो नहीं होने जा रही जैसे कि वहां पर यह मांग की जा रही है कि इस का ऐडमिनिस्ट्रेशन जो इसके पास के देश इंडोनेशिया और पाकिस्तान हैं, उन्हें दे दिया जाए . . . .

MR. SPEAKER : That portion of the question which relates to Indonesia need not be answered. Only that portion which relates to Ceylon need be answered.

**श्री जार्ज फरनेन्डीज** : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है । क्या सदन इसी तरह से चुपचाप बैठा रहेगा और भारत सरकार एक के बाद एक इलाका देती चली जाएगी । उस ने कच्छ छोड़ दिया और अब सीलोन की बात आई है मन्त्री जी ने बतलाया है कि वहां सीलोन के हाई कमिश्नर से पूछ रहे हैं तो उन से क्या पूछ रहे हैं ? आप अपनी आर्मी नेवी और ऐयर फोर्स से पूछिए । क्या कुछ भी देश की मुहब्बत आप के दिलों में बाकी नहीं रही है . . . . . .

MR. SPEAKER : Order, order. Will you kindly sit down now ? May I request the hon. Minister to answer that portion which pertains to Ceylon ?

**श्री ब० रा० भगत** : अध्यक्ष महोदय . . . . (**व्यवधान**)

**श्री मधु लिमये** : अध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस से मिल कर बातें करते हैं। मुझे सख्त ऐतराज है। जब दूसरे दल के लोग, रंगा साहब के लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं तो उन को रोकना चाहिए. . . . (**व्यवधान**)

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : He may be a senior Member. We are also here since 1957. He has always been elected through a bye-election.

MR. SPEAKER : He is in the middle of his answer. Shri Fernandez has asked a question and here is the Minister standing on his legs to answer that. For heaven's sake, let us cool our tempers.

**श्री ब० रा० भगत :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी पूछा। उन के शब्द यह थे "अगर सीलोन ने कब्जा किया हो तो हम क्या कर रहे हैं ?" अब जाहिर है कि हाइपोथिटिकल क्वैश्चन है। मैंने यही कहा कि यह समाचार आया है बाकी जब तक अधिकारिक तौर पर हमें इस बारे में कुछ मालूम न हो जाय तब तक.....

SHRI S. M. BANERJEE : A time is coming when only Allahabad and Rae Bareli will remain in India.

**श्री ब० रा० भगत :** तब हम कुछ निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं। हम सीलोन सरकार से बातचीत कर रहे हैं पता लगा रहे हैं और बाद में पूरी जानकारी देंगे। कोई माननीय अगर हाइपोथिटिकल क्वैश्चन पूछें तो उस का जवाब नियम के अनुसार दिया भी नहीं जाता है..... (**व्यवधान**)

**कुछ माननीय सदस्य :** क्या सरकार कच्छ की तरह सीलोन को भी सौंपने को तैयार हो रही है ? मन्त्री महोदय आखिर बतला क्या रहे हैं ? (**व्यवधान**)

MR. SPEAKER : What is the use ? It would not be answered. Shri Swell.

SHRI SWELL (Autonomous Districts) : The newspaper report says that the Government of India put forward its claim to this island only in 1956. I want to know whether at any time that Government put forward its claim to this island and, if it has done that, does it accept the position that this island is in dispute between India and Ceylon. Why did they put the claim only in 1956 ? What was the position before that ? In whose possession was this island ?

SHRI B. R. BHAGAT : This matter relates even to an earlier period. The matter arose as far back as 1921 also. So far as the possession of the island is concerned, this island is completely uninhabited, nobody lives there. There is not even water there. Therefore, it is in nobody's possession.... (*Interruption*).**

** Not recorded.

MR. SPEAKER : The House would like to hear the answer, not you alone. You will have to sit now. Nothing will be taken down.

SHRI SWELL : My question has not been answered. The Minister is trying to play down the whole thing by saying that that island has not even water there. I would like to know in whose possession the island was.

SHRI B. R. BHAGAT : I said that it is neither under the possession of India nor of Ceylon.... (*Interruption*).

SOME HON. MEMBERS : Shame, shame.

SHRI G. VISWANATHAN (Wandiwash) : He cannot say that in the House.... (*Interruption*).

SHRI S. KUNDU (Balasore) : Let the Prime Minister clarify this point now made by the Minister. It is a very serious point that he has made.

MR. SPEAKER : Will you kindly sit down ? Shri Madhu Limaye. His name is there.

**श्री मधु लिमये :** अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री ने अपने उत्तर में दो बातें कहीं। एक यह कि हाई कमिश्नर से अब तक इन को कोई जानकारी नहीं है और दूसरी बात उन्होंने यह कही कि हमारा इस द्वीप पर कब्जा नहीं था। यह दो बातें साफ कहीं हैं। (**व्यवधान**)

**श्री रणवीर सिंह** (रोहतक) : नहीं कहा है। (**व्यवधान**)

MR. SPEAKER : Order, order.

**श्री मधु लिमये :** यह बात पहले साफ हो जाए। उन्होंने कहा कि नहीं कहा है। हम सब कहते हैं कि कहा है। पहले मन्त्री महोदय इस को बतलायें, नहीं तो हमारे प्रश्न पूछने से क्या फायदा है ?

**श्री हुकम चन्द कछवाय** (उज्जैन) : प्रधान मन्त्री से जवाब दिलवाया जाए।

**श्री ओंकारलाल बेरवा** (कोटा) : प्रधान मन्त्री को स्पष्टीकरण करना चाहिए।

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** वह कब तक गूंगी बन कर बैठी रहेंगी ?

MR. SPEAKER : I do not think it will be possible to conduct the proceedings of the House in this way. It is impossible now. (*Interruptions*) I cannot help it. After all, the Opposition, some of them, have their own opinions and other Members also have their own opinions. I can only regulate the proceedings. Nothing more can be done. This is a Call Attention Notice. I would like my friends to ask a question, a clarification.... (*Interruption*) I am saying for myself. Sitting in the Chair, I have no opinion either way. I can only regulate the proceedings of the House. That is only left to the Speaker. If so many of you begin getting up and shouting, it will be difficult for me. Shri Madhu Limaye is putting a question. (*Interruption*) If the Prime Minister thinks it necessary that she should answer, I will be happy. She may do it herself also. But, in the meanwhile, if you don't allow the question and in between so many of you get up and shout, it will be very difficult for me. I want your cooperation. It is an important question. The Prime Minister is fortunately here. She has got other duties also. I can sympathise with the Prime Minister. She has so many responsibilities.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, कम से कम मैंने यह सुना है कि हाई कमिश्नर के पास से कोई रिपोर्ट नहीं आई है और यह कि इस वक्त अपना कब्जा नहीं है, न पुलिस न सैनिकी। इस माने में कब्जा नहीं था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात का पता है कि भूतपूर्व रामनाड रियासत के कब्जे में यह रहा है, और जब रामनाड रियासत का विलीनीकरण मद्रास के साथ हुआ तो वह रामनाडपुरम जिले का अविभाज्य हिस्सा हुआ ? यदि यह बात सही है तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जो हमारे दूर के सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे समुद्र में हों या जैसे लद्दाख और कच्छ के इलाके में कंजरकोट हो, उन में गश्त लगाने और वहां चेक-पोस्ट कायम करने का काम करें। जिस को आप अपना कारगर नियन्त्रण अथवा एफेक्टिव अकुपेशन या कंट्रोल कह सकते हैं ? ऐसा करने के बारे में जो ढिलाई बरती गई उस से यह हमारे दूर के सीमावर्ती इलाके विदेशों के कब्जे में जा रहे हैं और तरह-तरह के दावे किये जा रहे हैं। इस तरह के विवाद खड़े किए जाते हैं और फिर आप पंचों के सामने जाते हैं, आरबिट्रेशन में जाते हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मैंने जिन बातों की ओर उन का ध्यान दिलाया है, क्या वह सही है। यदि वह सही हैं तब इस द्वीप को, जिस को कच्छ तीवु कहते हैं, अपने कब्जे में करने के लिए सरकार क्या कर रही है।

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : May I say a few words ? I appreciate the anxiety of the hon. Members. As the Minister tried to explain earlier, we do not have the full information at this moment. We have had very friendly relations with the people and the Government of Ceylon, and, I think, the more we say on this issue just now, the more are the chances that it may create difficulties. It is better to have fuller information which the Minister has already promised. We will make a statement.... (*Interruption*). About occupation, if you mean by the army, he has said that nobody is in occupation. This does not mean title or sovereignty.... (*Interruption*).

MR. SPEAKER : She has not yet replied fully.

श्री मधु लिमये : मैंने सैनिकी या पुलिस अथवा सिविल कंट्रोल के बारे में कहा था।

SHRIMATI INDIRA GANDHI : As the Minister has stated, this is an uninhabited island. There is occasionally, I think, some religious function to which people go there. I think, with your permission, if the hon. members would be a little patient and wait for us to get fuller information....

SHRI RABI RAI (Puri) : When ?

SHRIMATI INDIRA GANDHI : I think, on Monday; we can try on Monday.

MR. SPEAKER : May I suggest one thing ?

**श्री मधु लिमये:** उस के बाद क्या हम को सवाल पूछने दिया जायेगा ? मेरे प्रश्न के उत्तर में प्रधान मन्त्री ने कहा कि वह सोमवार को इत्तला देंगी। क्या इस के बाद हम को सवाल पूछने को इजाजत दी जाएगी?

MR. SPEAKER : Please sit down. She has said.... (*Interruptions*).

SHRI RANDHIR SINGH : Where is the question of possession ?

MR. SPEAKER : He should address the Chair.

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार के पास इस समय पूरी जानकारी नहीं है तो सरकार जानाकरी प्राप्त करे। लेकिन यह द्वीप भारत का भाग है या नहीं यह सीलोन से आने वाली जानकारी पर निर्भर नहीं करता। इस प्रश्न को सरकार को सन्देहावस्था में नहीं छोड़ना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री यह बात सदन में कहें कि यह द्वीप भारत का भाग है। इस समय उस की स्थिति क्या है, इस के बारे में वह जानकारी प्राप्त करें, लेकिन जहां तक उस के भारत का भाग होने का प्रश्न है, इस को वह सन्देह में न डालें।

SHRI NATH PAI (Rajapur) : May I humbly ask you. ....

MR. SPEAKER : He may please sit down. I will call him again, if necessary.

Instead of having a debate on this, now, we can do this. The Prime Minister has said that on Monday they are going to have fuller information and then, if necessary, I will allow a half-an-hour discussion or something. She is not in a position to say anything now and she also says that it will complicate matters if anything is said now. This is a call-attention.... (*Interruptions*).

SHRI S. M. BANERJEE *rose*—

MR. SPEAKER : He may sit down. I am on my legs. This is concerning Ceylon and that island, Kuchchativu. He cannot bring in Andaman and all that. The budget debate is coming, the foreign affairs debate is coming, and he can take up these points at that time.... (*Interruptions*).

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. SPEAKER : All of them may please sit down. I have requested Mr. Nath Pai and others also to sit down.

SHRI RANDHIR SINGH : The reply from the Prime Minister is very intelligent. It is not a question of possession.

MR. SPEAKER : He may sit down. I have requested Mr. Nath Pai and the others also to sit down and they are sitting.

**श्री रणधीर सिंह** : वह नेशन के खिलाफ बात करते हैं।

MR. SPEAKER : May I request the hon. Member to sit down ? Only one point is relevant. Whether this island belongs to us or not is the point. I can understand that. If the hon. Minister can answer now, it is well and good; or else on Monday.... (*Interruptions*). I am giving the hon. Minister a chance now; or else, when they make a fuller statement on Monday, naturally I will.... (*Interruptions*). I have not finished my sentence and hon. Members are interrupting me. I would make a request to the hon. Members. As and when I ask them to make a statement and I allow a half-an-hour discussion if I am asked again that all the parties must get a chance and all that, it would be difficult; if anybody wants to put a question on this, he may let me know about it in advance and I will allow about half a dozen questions to be put.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi) : The damage has been done.... (*Interruptions*).

AN HON. MEMBER : They should withdraw the statement that it is not a part of India.

SHRI NATH PAI *rose*—

MR. SPEAKER : I am not allowing any question to be answered by the Minister.

[Mr. Speaker]

The Prime Minister has said that she will get fuller information on Monday and give it to the members. About the correction, I am myself asking her. If she wants to say anything now, she can.

SHRIMATI INDIRA GANDHI : I have already explained. When the Minister was explaining the position, he was not talking of ownership or sovereignty. One other matter is that.... (*Interruptions*).

SHRI NATH PAI : I fully appreciate your sentiment and also the Prime Minister's sentiment that we should not say things which will complicate the issue. We agree with you on that point. I welcome your suggestion that we should not have a discussion now but we should have a proper discussion later on.

MR. SPEAKER : That is not necessary now. I thank him for welcoming the suggestion.

SHRI NATH PAI : I am raising a point of order. I am not asking a question.

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN (Chamba) : The Prime Minister has not finished her reply. So, why should the hon. Member be allowed to speak now ?

SHRI MANUBHAI PATEL (Dabhoi) : Why should he raise a point of order now ? Yesterday he started raising points of disorder.

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN : When the Prime Minister has not finished her answer, why should he be allowed to speak now ? (*Interruptions*).

MR. SPEAKER : Will the hon. Member kindly sit down now ? This kind of cross-talk does not help. What is the point of order ?

SHRI NATH PAI : This is the point of order.

I fully welcome what you have said namely that we should....

MR. SPEAKER : That is not a point of order.

SHRI NATH PAI : Let me complete what I was going to say. I have been interrupted systematically. (*Interruptions*) Sit down....

SHRI SONAVANE (Pandharpur) : He should sit down first.

MR. SPEAKER : He wants to raise a point of order. Let us hear the point of order.

SHRI NATH PAI : Shri B. R. Bhagat has said that Government have no information.... (*Interruptions*). Sit down. *Zarda suno to*.... (*Interruptions*).

श्री रणधीर सिंह : जवाब देने दें । तो जवाब नहीं देने दिया जाता है....

MR. SPEAKER : The hon. Member may leave it to me to control the House.

श्री मनुभाई पटेल : इतने गुस्से से क्यों बोलते हैं ?

Why should he get excited ? Why should he give sermons to us today ? Yesterday what was the lesson that he gave us ?

SHRI NATH PAI : Shri B. R. Bhagat had told the House....

श्री प्रेम चन्द वर्मा (हमीरपुर) हम भी चुन कर आए हैं । हम भी....

SHRI NATH PAI : I do not want to yield.

श्री प्रेम चन्द वर्मा....इस हाउस के मेम्बर हैं । उनकी क्या हिम्मत है कि इस तरह से बोलें ।

श्री रणधीर सिंह : इस पर लगाम लगाओ ।

SHRI NATH PAI : By shouting he cannot intimidate us. He cannot shout in this manner.

MR. SPEAKER : Two mistakes do not make one right.

SHRI MANUBHAI PATEL : Shri Nath Pai is a senior Member. Should a senior Member behave like this ?

SHRI NATH PAI : May I frame my point of order ?

श्री रणधीर सिंह : क्या उन्होंने हाउस को बैं कर रखा है ?

What does he think of himself ?

कल इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को इटरप्ट किया था ।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : यह क्या बात है ? हम इस बात को नहीं मानते हैं ।

SHRI NATH PAI : I am sure he would not like to hear what I think of him.

SHRI RANDHIR SINGH : We strongly protest against this kind of thing.

SHRI NATH PAI : I have been called by you and I am in possession of the floor. So, may I continue ? On the 7th....

SHRI RANDHIR SINGH : Do not allow him, Sir. He is monopolising the time of the House. Who is he to monopolise the time of the House ? You are allowing him to say all kinds of irrelevant things.

SHRI MANUBHAI PATEL : Under what rule is he raising the point of order ? Let him state the rule and then raise the point of order.

SHRI NATH PAI : The Minister of External Affairs in his earlier reply stated that Government had no information.

SHRI MANUBHAI PATEL : Under what rule is he raising the point of order ?

MR. SPEAKER : Under what rule is he raising it ?

SHRI NATH PAI : Under rule 370.

SHRI HEM BARUA (Mangaldai) : May I point out that the trouble is because there is no leadership in the Congress Party. There was a time when Shri Jawaharlal Nehru was alive and when Shri Lal Bahadur Shastri was alive, when people could not stand on their hind legs and shout like this. Now, even when the Prime Minister beckons to them to sit down, they jump on their hind legs and shout. That is the trouble.

SHRI NATH PAI : I do not want a reply from him today. I welcome your suggestion that there will be a discussion at the proper time. I am pointing out the total contradiction in the reply given.

We raised this question on the 7th August 1967 and the reply then given was—I am quoting from the proceedings of the House....

MR. SPEAKER : How can that be a point of order ?

SHRI NATH PAI : It is only when you hear me in full you will know.

On the 7th August 1967, a question was asked by Shri Kiruttinan of the DMK. It was addressed to the Minister of External Affairs. It read :

> "whether it is a fact that there is a church built up by Indian fishermen in the Katcha Dive near Rameswaram;
>
> whether it is also a fact that the people from Ceylon and Government officials and Navy forces of the Ceylon Government are freely allowed to enter into the Island, and take away all the income of the church to Ceylon;
>
> if so, the action taken by Government in this regard ?"

This was in August 1967. Today we are in March 1, 1968, six months later. What was the reply then ?

"Government have no information". Six months later, we are told 'Government have no information'.

Shri B. R. BHAGAT : Let him please read the whole of the sentence of the first reply.

MR. SPEAKER : There is no point of order.

SHRI NATH PAI : I have not concluded.

MR. SPEAKER : You can have your own way—I do not mind. You are only pointing out the difference between what they said then and what they said now.

SHRI NATH PAI : No, Sir. Six months later, they cannot reply. If you still think there is no point of order, do I take it that they are not required to answer questions ?

SHRI MANUBHAI PATEL : This was what I submitted earlier. Under cover of a point of order, he raises certain questions.

SHRI NATH PAI : They are required, under the rules, to answer questions.

MR. SPEAKER : No. ....

SHRI NATH PAI : No ? Is it your ruling that they are not required to answer questions.

MR. SPEAKER : I said there is no point of order.

SHRI NATH PAI : It has taken them 7 months to answer a question. Why ?

MR. SPEAKER : There is no point of order. The Minister shall not reply to his question. It is happening every day, and a debate is being held on a point of order. I am a helpless witness to this. It is unfortunate. If something was said on an earlier occasion and something else is said now, it cannot be the subject of a point of order. He can raise an objection. This is a delicate matter in which the Prime Minister....

SHRIMATI INDIRA GANDHI : I only wanted to say that the hon. Member read only half the sentence.

SHRI NATH PAI : No, no.

SHRIMATI INDIRA GANDHI : After reading out the question, from the answer the hon. Member read out : 'Government have no information..' and stopped there. The full answer was :

> "Government have no information that this church has any income. It is understood that religious ceremonies are held in the church once a year, which are attended by Indians and Ceylonese".

MR. SPEAKER : Papers to be laid on the Table Dr. V. K. R. V. Rao.

श्री मधु लिमये : प्वाइंट आफ आर्डर का क्या हुआ है ?

MR. SPEAKER : No point of order.

---

12-38 HRS.

## PAPERS LAID ON THE TABLE

### ANNUAL ACCOUNTS OF THE KANDLA PORT TRUST

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH) : On behalf of Dr. V. K. R. V. RAO, I beg to relay on the Table a copy of the Annual Accounts of the Kandla Port Trust for the year 1965-66 and the Audit Report thereon, under sub-section (2) of section 103 of the Major Port Trusts Act, 1963. [*Placed in Library, See* No. LT-271/68].

### ANNUAL REPORT OF INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KHARAGPUR AND UNIVERSITY GRANTS COMMISSION AMENDMENT RULES

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) : I beg to lay on the Table—

(1) (i) A copy of the Annual Report of the Indian Institute of Technology, Kharagpur, for the year 1965-66.

(ii) A statement showing reasons for delay in laying the above Report. (*Placed in Library, See* No. LT-272/68] .

(2) A copy of the University Grants Commission (Terms and Conditions of Service of Employees) Amendment Rules, 1968, published in Notification No. G. S. R. 258 in Gazette of India, dated the 10th February, 1968, under sub-section (3) of section 25 of the University Grants Commission Act, 1956. [*Placed in Library See* No. LT-273/68].

### ACTION TAKEN BY GOVERNMENT ON ASSURANCES, PROMISES AND UNDERTAKINGS

DR. RAM SUBHAG SINGH : I beg to lay on the Table the following statements showing the action taken by Govern-